LOK SABHA

———

Tuesday, August 16, 1983

Srawana 25, 1905 (Saka)

———

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Bombay Pune Petroleum Pipeline Project

*308. SHRI **J.S. PATIL** : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the present status of the Bombay-Pune Petroleum Product carrying pipeline project.

(b) the salient features of this project, and

(c) when the same is likely to be commissioned ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) पाइपलाईन प्रायोजना के लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा अधिकतर पाइप और अन्य सामग्री प्राप्त कर ली गयी है । मुख्यलाईन के निमाण के लिये संविदा प्रदान करने के लिये एक आशय पत्र जारी कर दिया गया है तथा लगभग 4-5 सप्ताह में कार्य शुरू हो जाने की आशा है ।

(ख) (1) इसमें 14" व्यास की 158 किलो मीटर पाइपलाईन डालने का प्रस्ताव है जो कि बम्बई रिफाइनरी को लोनी स्थित टर्मिनल के साथ जोड़ेगी ।

(2) इस पाइपलाईन द्वारा मोटर स्पिरिट, मिट्टी का तेल हाई स्पीड डीजल तेल तथा लाईट डीजल तेल जैसे उत्पाद ले जाये जायेंगे ।

(3) पाइपलाइन की प्रारम्भिक क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष डिजायन की गयी है तथा बाद में इसमें इंटरमीडियेट बूस्टर स्टेशनों की स्थापना करके 4.2 मि.मी. टन प्रति वर्ष (89-90) तक बढ़ाने की व्यवस्था भी की गयी है ।

(4) पाइपलाईन प्रायोजना तथा टर्मिनल पर लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

(ग) पाइपलाइन को 1982 के अन्त से पूर्व यांत्रिक दृष्टि से पूरा किया जाना तथा पाइपलाइन को आरम्भ किया जाना है ।

श्री जगन्नाथ पाटिल : इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी जानकारी चाहिए उतनी मंत्री महोदय की और से दी गई और विवरण में ऐसा बताया कि चार पांच सप्ताह में इस प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत होगी । अगर मंत्री महोदय जैसा कहते हैं उस तरीके से सही ढग से शुरुआत हो गई तो मैं ऐडवांस में उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है उनको उसका मुआवजा दे दिया है या नहीं ? अगर नहीं है तो कब तक दे देंगे ? इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद वहां के स्थानीय लोगों को जो वहां नौकरियां उपलब्ध होंगी वह दी जायेंगी या नहीं ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : जहां तक धन्यवाद देने का सवाल है मैं संसद सदस्य महोदय की प्रशंसा करता हूं और जहां तक काम शुरू करने का प्रश्न है जिस प्रकार से बारिश आ रही है, आप को तो पता है आप स्वयं थाने से आते हैं, बारिश के बाद ही काम शुरू हो पाएगा । आप ने सवाल किया कि जमीन का जो अधिग्रहण किया गया है उसके मुआवजे का क्या होगा तो यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है । उन के द्वारा ही भूमि का अधिग्रहण किया जाता है । उस के लिए जितना रुपया आवश्यक होता है वह हम स्टेट गवर्नमेंट के पास डिपाजिट कर देते हैं ।

तीसरी चीज आपने यह पूछी है कि जिनकी जमीन ली गई है, क्या उनको कार्य दिया जायेगा - इस पर हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ।

श्री जगन्नाथ पाटिल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट का प्लान एस्टिमेंट जब तैयार किया गया तब इसका खर्चा अन्दाजे से 55 करोड़ बताया गया । मैं जानना चाहता हूं यह प्रोजेक्ट, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, 1984 में पूरा होगा लेकिन जिस ढंग से सरकार के सारे काम चल रहे हैं उनका देखते हुए यह 1984 में पूरा हो जायेगा, ऐसा नहीं लगता है परन्तु जब भी यह पूरा होगा तब इस प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ का खर्चा बढ़ जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अभी से क्यों चिन्ता करते हैं, काम करवाने दीजिए ।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी नहीं । मैं आपकी बात के साथ नहीं चल सकता क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं होगा और हम कहते हैं होगा ।

Decision to Curb Trade Union Growth

*310. SHRI AMAR ROYPRADHAN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to curb trade union growth; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI AMAR ROYPRADHAN : Mr. Speaker, Sir, the reply is vaque. Please help me to get a correct reply. I think, the hon. Minister is not giving to the House a true and honest reply.

The hon. Minister while inaugurating a lecture on the Seminar on "Changes in Industrial Relations in 80s" held in Bombay on 21st May, 1983 under the auspices of the All India Manufacturers' Organisation said :

> "...for healthy growth of trade unions some legislation is essential to curb the formation of trade unions."

Sir, this statement of the Minister provoked me to put this Question.